



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/ आषाढ़ 17, 1937

No. 188]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASHADHA 17, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2015

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अनधिक के बाह्य व्यास के हाट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रान अथवा कोल्ड रोलड आयरन, अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त) के सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और हालो प्रोफाइल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फाइल संख्या 14/2/2015-डीजीएडी.- यतः, आईएसएमटी लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (जिन्हें एतद्पश्चात आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदनपत्र चीन जन.गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अनधिक के बाह्य व्यास के हाट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रान अथवा कोल्ड रोलड आयरन, अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त) के सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और हालो प्रोफाइल्स" (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए दायर किया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण करने का अनुरोध किया है।

2. और यतः, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि सम्बद्ध देश से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन होने, घरेलू उद्योग को "क्षति" होने, तथा पाटन एवं क्षति के बीच अभिकथित कारणात्मक संबंध होने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा किसी अभिकथित पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जाँच करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत एक जाँच की शुरुआत करते हैं जो अभिकथित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी राशि की सिफारिश करने, जो यदि उद्ग्नहीत की गई तो, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया गया है "355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अनधिक के बाह्य व्यास के हाट फिनिश अथवा कोल्ड ड्रान अथवा कोल्ड रोलड आयरन, अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त) के सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और हालो प्रोफाइल्स"। इस विचाराधीन उत्पाद में हाइड्रोकार्बन उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले बायलर पाइप्स अथवा लाइन पाइप्स और तेल एवं गैस अन्वेषण के लिए ड्रिलिंग में प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की केसिंग और ट्यूबिंग भी शामिल है। तथापि, निम्नलिखित उत्पादों को इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित रखा गया है :

- (i) एसटीएम ए 213/एसएमई एसए 213 और एसटीएम ए335/एसएमई एसए 335 अथवा समकक्ष बीआईएस/डीआईएन/बीएस/ईएन के विनिर्देशन के अथवा किसी अन्य समकक्ष विनिर्देशन के सीमलेस अलाय स्टील पाइप्स, ट्यूब्स और हालो प्रोफाइल्स।
- (ii) नान-एपीआई और प्रीमियम ज्वाइंट्स/प्रीमियम कनेक्शन्स/प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब्स और पाइप्स।
- (iii) सभी 13 क्रोमियम (13 सीआर) ग्रेड के ट्यूब्स और पाइप्स, और
- (iv) ड्रिल कालर्स

4. सीमलेस ट्यूब्स का प्रयोग वहां किया जाता है जहां सुदृढ़ता, संक्षारण प्रतिरोध शक्ति, माइक्रोस्ट्रक्चर और उत्पाद का जीवन बहुत संवेदनशील होता है। केसिंग और ट्यूबिंग का प्रयोग समुद्र के साथ-साथ जमीन से कूड ऑयल और गैस का निस्सारण करने में किया जाता है। लाइन पाइप्स का प्रयोग हाइड्रोकार्बन और प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। बायलर पाइप्स का प्रयोग बायलरों, ताप एक्सचेंजों, सुपर हीटर्स और कंडेन्सर्स तथा मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल और जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, रेलवे आदि में किया जाता है।

5. सीमलेस पाइप्स एवं ट्यूब्स को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 73 के सीमाशुल्क उप-शीर्षक संख्या 73.04 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग एवं आधार

6. यह आवेदनपत्र आईएसएमटी लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। जिन्दल सा लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) और रेमी मेटल्स लिमिटेड भारत में इस संबद्ध वस्तु के अन्य ज्ञात उत्पादक हैं। आवेदनपत्र में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों को उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 66.77 प्रतिशत बनता है। आवेदकों ने यह उल्लेख करते हुए एक घोषणा भी प्रस्तुत की है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है, और न ही उनका संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक/आयातक के साथ कोई संबंध है। आवेदनपत्र में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों का उत्पादन भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का एक "बड़ा अनुपात" बनता है। इसलिए, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदनपत्र पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5(3) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप आधार के मानदंड को पूरा करता है।

अंतर्ग्रस्त देश

7. वर्तमान जांच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण. है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा चीन जन.गण. से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। दोनों ही उत्पादों के कतिपय पैरामीटरों के गुणधर्म जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन.गण. से आयातित वस्तु को अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के रूप में समान है। घरेलू आयातित उत्पाद के तकनीकी रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन जन.गण. से आयातित संबद्ध वस्तु को नियमों के अनुसार घरेलू समान वस्तु के रूप में मानते हैं।

सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के संलग्नक-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाए। आवेदक ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया है। नियमावली के संलग्नक-1 के पैरा 8 के अनुसार यह प्रकल्पना की जाती है कि चीन जन. गण. में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। आवेदक ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर इसलिए नहीं किया जा सकता है कि उनसे संगत सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश की भारत सहित अन्य देशों को कीमत पर निम्नलिखित कारणों से भरोसा नहीं किया जा सकता है कि (क) संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है (ख) संक्षिप्त सीमाशुल्क सूचना पर इस कारण से भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है (ग) अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों (यूरोप, यूएसए और कनाडा) द्वारा आयोजित की जा रही जांचों में स्पष्टतः यह सिद्ध किया गया है कि चीन के उत्पादक विश्व की प्रमुख बाजारों में पाटन का आश्रय ले रहे हैं और इस प्रकार, अन्य देशों को निर्यात कीमत का भी निग्रहण होगा। अतः आवेदकों ने सामान्य मूल्य का दावा भारत में उत्पादन लागत, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लागत, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लाभ शामिल हैं, के आधार पर किया है। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रकल्पना और चीन जन.गण. के प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अध्यधीन को ध्यान में रखते हुए चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के संलग्न 1 के पैरा 7 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया गया है।

निर्यात कीमत

10. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर विचार करते हुए किया गया है। फैक्ट्री बाह्य निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्यातक देश में समुद्री भाड़ा, अंतर्भू भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, वैट को ध्यान में रखते हुए कीमत समायोजन किया गया है।

11. संबद्ध देश के संबंध में सामान्य मूल्य की तुलना फैक्ट्री बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत से की गई। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि चीन जन.गण. में इस तरह संबद्ध वस्तु का निर्धारित सामान्य मूल्य फैक्ट्री बाह्य निर्यात कीमत से अधिक हैं, इससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। आकलन किया गया पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. आवेदक ने क्षति पैरामीटरों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। इस सूचना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि यद्यपि आयातों में गिरावट आई है परंतु आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कुल आयातों में संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के हिस्से में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू कीमतों का भारी अधोरदन कर रहे हैं और इन आयातों का प्रभाव कीमतों में वृद्धि को निवारित करना है जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में प्रदान कराई गई सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मूल्य और मात्रा, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह, मालसूची और बाजार हिस्से के रूप में वास्तविक गिरावट आई है। वास्तविक क्षति के अलावा आवेदकों ने घरेलू एवं आयातित उत्पाद की कीमतों, संबद्ध देशों द्वारा आयोजित की जा रही मौजूदा जांच के आधार पर वास्तविक क्षति की चुनौती का भी दावा किया है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को चीन जन.गण. के पाटित आयातों से क्षति कारित की गई है जो नियमावली के अंतर्गत पाटनरोधी जांच की शुरुआत करना न्यायोचित ठहराती है।

जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और जांच की अवधि भी शामिल होगी।

शुल्क का पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिरोपण

14. आवेदक ने शुल्क का अधिरोपण पूर्वव्यापी प्रभाव से करने का अनुरोध किया है क्योंकि घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति सम्बद्ध उत्पाद के काफी पिछले समय से भारी पाटन द्वारा कारित की गई है। उन्होंने पुनः यह प्रस्तुत किया है कि इन आयातों की भारी मात्रा और घरेलू

उद्योग को क्षति पर विचार करते हुए, जब तक इस शुल्क का पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिरोपण करने की सिफारिश नहीं की जाती है तब तक पाटनरोधी शुल्क के वांछित उपचारी उपाय पूरे नहीं कहे जा सकेंगे। हितवद्ध पक्षकार इस सम्बंध में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

15. सम्बद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों तथा सम्बद्ध देशों की सरकार को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए, भारत में इस संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत कर सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

समय-सीमा

16. वर्तमान जांच से संबंधित किसी सूचना को लिखित रूप में इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से (40 दिनों) से अनधिक समय में पहुँच जाए। तथापि, ज्ञात निर्यातकों और आयातकों, जिन्हें अलग से संबोधित किया जा रहा है, कि वे उन्हें अलग से प्रेषित पत्र की तारीख से 40 (चालीस) दिनों के अंदर सूचना प्रेषित करें, यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय-सीमा में विस्तार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली प्रत्युत्तर/प्रस्तुतीकरण के किसी भाग पर यदि गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो पृथक सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (क) गोपनीय के रूप में (शीर्षक, अनुक्रमणिका, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) के रूप में चिन्हित तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय (शीर्षक, अनुक्रमणिका, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) के रूप में चिन्हित होना चाहिए। प्रस्तुत की गई सभी सूचना को स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर चिन्हित किया जाना चाहिए।

18. किसी गोपनीय चिन्हांकन के बिना की गई प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में समझा जाएगा और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि ऐसी प्रस्तुतिकरण का निरीक्षण करने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षकारों को अनुमति प्रदान करें। सभी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

19. "गोपनीय" के रूप में दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता से सूचना के साथ उन कारणों का विवरण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है कि उक्त सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/अथवा उक्त सूचना को संक्षेप में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

20. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की पर्याप्त समक्ष स्पष्ट हो जाए, ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

21. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना

को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने पर और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप में प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी ऐसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Department of Commerce

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2015

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD”, originating in or exported from China PR.

F.No.14/2/2015-DGAD - Whereas ISMT Ltd and Maharashtra Seamless Ltd (hereinafter also referred to as applicants) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules), alleging dumping of Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) and requested for initiation of anti-dumping investigation and for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country and injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exists, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation has been defined as “Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD”. The product under consideration includes boiler pipes or line pipes used in hydrocarbon industry and casing and tubing of a kind used in drilling for oil and gas exploration. However the following products have been excluded from the scope of product under consideration:

- i. Seamless alloy-steel pipes, tubes and hollow profiles of specifications of ASTM A213/ASME SA 213 and ASTM A335/ ASME SA 335 or equivalent BIS/DIN/BS/EN or any other equivalent specifications.
- ii. Non - API and Premium Joints/Premium Connections/Premium Threaded Tubes & Pipes.
- iii. All 13 Chromium (13CR) Grade Tubes and Pipes, and
- iv. Drill Collars.

4. Seamless tubes are used where strength, resistance to corrosion, microstructure and product life is very crucial. Casing/tubing are used in extraction of Crude Oil and Gas from sea as well as from earth. Line pipes are used in hydrocarbon and processing industry. Boiler pipes are used in Boilers, Heat Exchangers, Super Heaters and Condensers, and in mechanical, structural and general engineering industry, Railways etc.

5. Seamless Pipes and Tubes are classified under Customs sub-heading No. 73.04 of Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

Domestic Industry and Standing

6. The application has been jointly filed by ISMT Limited and Maharashtra Seamless Limited. Jindal Saw Limited, Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL) and Remi Metals Ltd are the other known producers of the subject goods in India. As per information available in the application, the production of the applicants account for 66.77% of the total Indian production. The applicants have also furnished a declaration stating that they neither imported the subject goods from the subject country during the POI, nor are related to any exporter/importer of the subject goods from the subject country. From the information available in the application, the Authority notes that the production of the applicants accounts for “a major proportion” in the total production of the product under consideration in India. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Country Involved

7. The country involved in the present investigation is China PR.

Like Article

8. The applicant has claimed that there are no known significant differences in subject goods produced by the domestic industry and exported from China PR. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, tariff classification, etc. The goods produced by the domestic industry are comparable to the goods imported from China PR in terms of essential product properties. The domestic product is technically and commercially substitutable to the imported product. Therefore, for the purpose of present investigation, subject goods produced by the applicant are being treated as “Like Article” to the subject goods imported from China PR within the meaning of the Rules.

Normal Value

9. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and determined the normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for

China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 of Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. The applicant has submitted that normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not available to them. Further, they claimed that the price from market economy third country to other countries, including India, cannot be relied upon for the reasons (a) the relevant information is not publicly available, (b) summary customs information cannot be relied upon for the reason that the product under consideration does not have dedicated customs classification, (c) the investigations being conducted by other investigating authorities (Europe, USA and Canada) clearly establishes that the Chinese producers are resorting to dumping in major global markets and thus the export price to other countries would also be suppressed. The applicant has therefore, claimed normal value based on cost of production in India, including selling, general & administration expenses and reasonable profit. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from china PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

Export Price

10. Export price of the subject goods from the subject country has been determined by considering transaction wise import data collected from the DGCI&S. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, marine insurance, commission, port expenses, VAT, etc in the exporting country to arrive at ex-factory export price.

Dumping Margin

11. Normal value and export price have been compared at ex-factory level in respect of the subject country. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in China PR, so arrived is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from subject country into the Indian market and the dumping margin is estimated to be above *de minimis*.

Injury and Causal Link

12. The applicant has furnished information on various parameters relating to material injury. Analysis of the information shows that although imports have declined, but the share of imports from subject country to total imports has significantly increased during the POI as compared to the base year. The share of imports of subject goods from the subject country has also increased in relation to production & consumption in India. Imports of the product under consideration are significantly undercutting the domestic prices and the effect of such imports was to prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree. On the basis of the information provided with regard to various economic parameters relating to the domestic industry, it is seen that the performance of the domestic industry materially deteriorated in terms of production, capacity utilization, domestic sales value & volume, profits, return on investments, cash flow, inventories and market share. In addition to material injury, the applicant has claimed threat of material injury on the grounds of significant difference in the domestic and imported product price, ability of the subject exporters to export significantly higher volumes, current investigations being conducted by other countries. There is sufficient evidence that the injury to the domestic industry has been caused by dumped imports from China PR to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of the Rules.

Period Of Investigation

13. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st January, 2014 to 31st December, 2014 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI.

RETROSPECTIVE IMPOSITION OF DUTIES

14. The applicant has requested for retrospective imposition of duty as the injury is claimed to be caused to the domestic industry by a history of massive dumping of subject goods. They have further submitted that considering the huge volume of such imports and injury to the domestic industry, unless duty is recommended retrospectively, the

desired remedial measures of anti-dumping duties may not be accomplished. The interested parties may make their submissions in this regard.

Submission of Information

15. The known exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
4th Floor, Jeevan Tara Building
5 Parliament Street
New Delhi - 110001**

TIME LIMIT

16. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the Anti-dumping Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

23. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

NON-COOPERATION

24. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority